गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

# गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 277
दि. 08.02.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# कुआलालंपुर में फिर दिखी पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी, खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच चुके हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया की तीसरी आधिकारिक यात्रा है और द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है।

मलेशिया पहुंचकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम उन्हें रिसीव करने के लिए खुद पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कुआलालंपुर पहुंच गया हूं। एयरपोर्ट पर मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत खुश हूं। मैं हमारी बातचीत और भारत और मलेशिया के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करने के लिए

उत्सुक हूं।"

पीएम मोदी ने अनवर इब्राहिम के साथ शेयर की कार वाली तस्वीर

साथ ही उन्होंने अनवर इब्राहिम के साथ कार में फोटो भी शेयर करते हुए कहा, "भारत-मलेशिया के लोगों के बीच संबंधों का जश्न मना रहे हैं! मैं और पीएम अनवर इब्राहिम कुआलालंपुर में कम्युनिटी प्रोग्राम में जा रहे हैं।"

पीएम मोदी ने बताया किन मुद्दों पर होगी बात

प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले एक बयान में बताया गया कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत में रक्षा और सुरक्षा में सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक और इनोवेशन संबंधों को मजबूत करने और आपसी हित के उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

आज शाम प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में "सेलामत दातंग मोदी जी" नाम के एक कम्युनिटी रिसेप्शन में शामिल होंगे, जिसमें भारतीय मूल के लगभग 15,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

## पीएम मोदी ने कुआलालंपुर, मलेशिया में एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया

**आज दुनिया भारत को विकास के एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में में देखती है, चाहे यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ हो या अमेरिका— सभी देश भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, आज भरोसा ही भारत की सबसे बड़ी मुद्रा (करेंसी) बन गया है : प्रधानमंत्री**

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है, वह हमारी साझा संस्कृति की सुंदर विविधता को दर्शाती है। उन्होंने इस उत्सव में शामिल होने के लिए अपने प्रिय मित्र, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम स्वयं उनका स्वागत करने एयरपोर्ट आए और अपनी कार में बैठाकर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाए। श्री मोदी ने कहा, "प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का यह विशेष भाव भारत के प्रति उनके प्रेम और सम्मान को दर्शाता है, साथ ही यहाँ मौजूद आप सभी लोगों के प्रति उनके आदर को भी प्रकट करता है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि 800 से अधिक नर्तकों द्वारा पूरी लय और ताल के साथ दी गई रिकॉर्ड सांस्कृतिक

प्रस्तुति आने वाले कई वर्षों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने इस शानदार प्रदर्शन के लिए सभी कलाकारों को बधाई दी। श्री मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वे तब से मित्र हैं, जब वे प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। उन्होंने सुधारों के प्रति प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के दृष्टिकोण, उनकी शानदार बौद्धिक क्षमता और 2025 में आसियान के अध्यक्ष के रूप में उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि वह पिछले साल आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया नहीं आ पाए थे, लेकिन तब उन्होंने जल्द ही यहाँ आने का वादा किया था और आज उन्होंने अपना वह वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने बताया कि साल 2026 की यह उनकी पहली विदेश यात्रा है और उन्हें खुशी है कि वे त्योहारों के इस मौसम में भारतीय समुदाय के बीच हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी ने संक्रांति, पोंगल और थाइपुसम का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया होगा। उन्होंने आगे आने वाले त्योहारों—शिवरात्रि, रमजान की शुरूआत और हरि राया के लिए भी सभी को ढेरों शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।+

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मलेशिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय मूल का समुदाय निवास करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और मलेशिया के लोगों के दिलों को जोड़ने वाली बहुत सी बातें हैं। कार्यक्रम से पहले देखी गई एक प्रदर्शनी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें दोनों देशों के रिश्तों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है।

## 'हम भी आपके दादा लगते हैं' सीएम योगी ने अपने गांव पंचूर में किया रात्रि विश्राम, लोगों से मिले

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वह शुक्रवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने गांव में ही रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह वह अपने गांव की सैर पर निकले और बड़े-बुजुर्गों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और उनका बाल प्रेम उमड़ आया।

बच्चे से बोले- हम भी तुम्हारे दादा जैसे

गांव में भ्रमण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बड़े-बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और टाफियां दी। एक बच्चे को उन्होंने चॉकलेट दी तो वह अपने दादा को देने लगा तो सीएम ने कहा कि हम भी तुम्हारे दादा जैसे हैं। यह चॉकलेट आप खा लो यह खाने की चीज है।

उन्होंने गांव के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाया, उनसे देर तक बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दी। सीएम योगी ने एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे प्रेम से खिलाया। बच्चों ने भी सहज भाव से मुख्यमंत्री से बातचीत की। इस दौरान, गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी भी ली।

शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे थे सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे थे। उन्होंने और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित बिथ्याणी में जनता इंटर कॉलेज के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यह नीति विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने की बजाय उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

## योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई नेताओं ने रमाबाई आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी

लखनऊ, सात फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई प्रमुख नेताओं ने शनिवार को रमाबाई आंबेडकर की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी।

सीएम योगी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति, नारी चेतना की सशक्त प्रतीक माता रमाबाई आंबेडकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शिक्षित व जागरूक समाज के निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "महिला सशक्तिकरण की आदर्श प्रतीक एवं सामाजिक समानता की

## राष्ट्रपति ने जगदलपुर में बस्तर पैंडम 2026 का उद्घाटन किया

(एजेंसी)।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (7 फरवरी, 2026) जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में बस्तर पैंडम 2026 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जब किसान इस उपजाऊ भूमि में बीज बोते हैं, जब आम का मौसम आता है, तो यह पैंडम का मौसम होता है। बस्तर के लोग जीवन के हर पहलू का उत्सव मनाते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य लोग बस्तर के लोगों से जीवन जीने का यह तरीका सीख सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर की परंपराओं और संस्कृति ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन दुर्भाग्य से, यह क्षेत्र चार दशकों तक माओवाद से ग्रस्त रहा। परिणामस्वरूप, यहां के लोगों को भारी कष्ट सहना पड़ा। युवा, आदिवासी और दलित भाई-बहन सबसे अधिक प्रभावित हुए। लेकिन, भारत सरकार

द्वारा माओवादी आतंक के खिलाफ उठाए गए निर्णायक कदमों के कारण, वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का माहौल अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का मार्ग त्याग रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पहले माओवादी गतिविधियों में शामिल थे और अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हथियार डालकर लोग सामान्य जीवन जी सकें और मुख्य धारा में लौट सकें। उनके लिए कई विकास और कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार की 'नियाद नेल्लानार योजना' ग्रामीणों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने यह देखकर खुशी जताई कि बस्तर में विकास के एक नये समय की शुरूआत हो रही है। हर गांव में बिजली, सड़कें और पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद पड़े स्कूल फिर से खुल रहे हैं और बच्चे कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद उत्साहजनक तस्वीर है जो सभी नागरिकों के लिए खुशी का स्रोत है।

राष्ट्रपति ने हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा में लौटने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की और उनसे संविधान और देश के लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों का कल्याण सरकार की विशेष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री-जनमान योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के लाभ सबसे वंचित आदिवासी गांवों तक पहुंच रहे हैं।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला है।

आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि इन क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने सभी अभिभावकों और संरक्षकों से अपने बच्चों को शिक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह छत्तीसगढ़ और भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपराएं आज भी गहरी जड़ों से जुड़ी हुई और जीवंत हैं। देवी दंतेश्वरी को समर्पित बस्तर दशहरा आदिवासी संस्कृति और भाईचारे का एक अनूठा उदाहरण है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए विकास को अपनाने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां के लोग समर्पित और मेहनती हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों, विशेषकर युवाओं से, राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित कल्याण और विकास योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रगति और समृद्धि छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकसित भारत के लिए बेहद जरूरी है।

## विधानमंडलों में गरिमा और मयार्दा कम होने पर चिंता व्यक्त की

**लोक सभा अध्यक्ष ने रचनात्मक आलोचना के माध्यम से सार्थक विधायी निगरानी पर बल दिया**

**सशक्त विधायक ही मजबूत लोकतंत्र का आधार हैं: लोक सभा अध्यक्ष**

**संवैधानिक जागरूकता और प्रक्रिया के समुचित ज्ञान से विधिनिमार्ताओं की विश्वसनीयता बढ़ती है : लोक सभा अध्यक्ष**

**बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा ने भारत की संसदीय व्यवस्था को वैचारिक आधार प्रदान किया है: लोक सभा अध्यक्ष**

**लोक सभा अध्यक्ष ने बिहार विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित किया**

**लोक सभा अध्यक्ष ने बिहार विधानमंडल में नेवा डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया**

(एजेंसी)।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज विधानमंडलों में गरिमा और मयार्दा कम होने पर चिंता व्यक्त की। विधायी संस्थानों की शुचिता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा और मयार्दा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की मूलभूत जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विधायिका लोकतंत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है और इसकी गरिमा का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए।

श्री बिरला ने विधायी कार्यवाहियों में व्यवधान और अमर्यादित आचरण की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक निकायों की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने सदस्यों से संवाद, तर्कसंगत वाद-विवाद और रचनात्मक चर्चा पर बल देने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि आलोचना नीतियों और तथ्यों पर आधारित तथा जनकल्याण की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। लोक सभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संसदीय अनुशासन और रचनात्मक आलोचना पर आधारित सार्थक विधायी निगरानी से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है । श्री बिरला ने ये विचार आज पटना में बिहार विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ह्यसशक्त विधायक, सशक्त लोकतंत्रह्व कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

यह टिप्पणी करते हुए कि सशक्त विधायक ही सशक्त लोकतंत्र का आधार होते हैं, श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता, दक्षता और सत्यनिष्ठा से जुड़ी होती है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों की प्रभावशीलता केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधायक को शक्ति जनता के विश्वास और भरोसे से प्राप्त होती है।

## भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे से मेक इन इंडिया और रोजगार को बढ़ावा: प्रधानमंत्री मोदी

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए तैयार किए गए ढांचे का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के लिए बड़ी और सकारात्मक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह ढांचा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की गहराई, विश्वास और सक्रियता को दर्शाता है तथा इससे मेक इन इंडिया अभियान को नई मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक्स पर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर की गई पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अंतरिम व्यापार समझौता किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप नवोन्मेषकों और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा तथा भरोसेमंद और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक विकास को भी गति मिलेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य उन्मुख वैश्विक साझेदारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो जनता को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि को बढ़ावा दे।

प्रधानमंत्री ने इसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए शानदार खबर बताया। उन्होंने कहा कि यह ढांचा दोनों देशों के बीच नवाचार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देगा तथा वैश्विक आपूर्ति तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंनें कहा कि भारत जैसे-जैसे विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वह ऐसी वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा जो जनता को केंद्र में रखती हों और विश्व स्तर पर साझा विकास में योगदान दें।

इससे पहले दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ यह महत्वपूर्ण ढांचा तैयार किया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर के विशाल अमेरिकी बाजार के द्वार खुलेंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, किसानों और मछुआरों को बड़ा लाभ मिलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। इस ढांचे के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, जिससे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बड़ी बढ़त मिलेगी। यह अवसर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाएंगे, जिनमें जेनेरिक दवाइयां, रत्न एवं आभूषण, हीरे और विमान कलपुर्जे शामिल हैं। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और अधिक सशक्त होगी। भारत को सेक्शन 232 के तहत विमान कलपुर्जों में छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक दवाओं को लेकर बातचीत के जरिए अनुकूल परिणाम मिले हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ठोस निर्यात लाभ सुनिश्चित होंगे।

उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की पूरी सुरक्षा करता है।

# सम्पादकीय

## नैतिक तौर पर तेजी से राजनीति का पतन

राजनीति का गिरता स्तर, अंकुश कौन लगाए, राजनीति के गिरते स्तर के चुनिन्दा उदाहरण मात्र हैं। पिछले कई वर्षो से देश में मिल-बैठकर देश की समस्याओं महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिचाई आदि पर राजनीतिक दलों में कोई बात नहीं हो रही है। राजनीति का गिरता स्तर, अंवुश कौन लगाए वैसे तो राजनीति का अभिप्राय राजकाज चलाने वाली नीति से है। इसका एकमात्र मकसद समतामूलक सुसय समाज का निर्माण करना और देश के चहुंमुखी विकास में योगदान देना है। लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यह क्षरण कहां जाकर थमेगा, पुख्ता तौर पर कोई नहीं कह सकता। यह गिरावट एक दिन में नहीं आयी है। आजादी के बाद हमारे संविधान निमार्ताओं और नीति नियंताओं ने काफी सोचवि चार कर समाज और देश के विकास का सपना देखा था। तब हमारी गिनती एक लुटे-पिटे गरीब देशों में होती थी। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने का दावा करते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर तेजी से पाताल की ओर गिरते जा रहे हैं। पिछले दिनों संसद के भीतरबाहर जो वुछ भी घटित हुआ, उससे हमारा लोकतंत्र और ज्यादा शर्मसार हुआ है। संसद के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक केन्द्रीय मंत्री को 'गद्दार दोस्त' कहकर पुकारा तो बदले में मंत्री ने उन्हें 'देश का दुश्मन' कह दिया। दोनों नेता कभी एक ही पाटा में साथ रह चुके हैं। दोनों के पुरखों का देश के विकास में योगदान रहा है। बात इतने में थम जाती तो गनीमत थी। लोग बाग मान लेते कि हम उम्र होने के कारण दोनों ने मजाक में वुछ बोल दिया। बात बराबर। लेकिन यह क्या? संसद में इस बात को लेकर बतंगड़ बना दिया गया। इसे समुदाय विशेष की अस्मिता से जोड़ दिया गया, खूब हंगामा हुआ। एक बड़बोले सांसद ने तो नेता प्रतिपक्ष को 'फटीचर' तक कह दिया। बेशक, तीनों ही शब्द माननीयों की गरिमा को गिराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब दूसरी घटना। लगभग 22 वर्षो बाद संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अपनी बात नहीं रख सके। इससे पहले 10 जून 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिह को तब के विपक्ष (अब सरकार में) के विरोध के कारण संसद में बोलने नहीं दिया गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए दोनों ही घटनाएं शर्मसार करनेवाली हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यह बयान देकर सनसनी पैला दी कि प्रधानमंत्री तो संसद में आकर अपनी बात कहने को इच्छुक थे, उन्हें मैंने ही सदन में आने से रोक दिया, क्योंकि उनके साथ वुछ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। सवाल उठता है कि क्या भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद में हमारे प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं? अगर, वाकई यह बात सही है तो बहुत ही दुखदाई है। प्रधानमंत्री को किससे सुरक्षा का खतरा है? संसद में तो जनता द्वारा चुने गए सांसद बैठते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष के बुलाने पर मार्शल आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को इसका खुलासा करना चाहिए। घटना की नामजद एफआईआर करानी चाहिए और नामजद व्यक्ति अगर संसद का सदस्य है तो उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और अगर यह बात सही नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष को अपने कहे के लिए देश से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। अगर, देश के प्रधानमंत्री अपनी ही संसद में असुरक्षित हैं तो फिर देश में सुरक्षित कौन है? गृहमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारी सुरक्षा एजेंसियां किसके आदेश का इंतजार कर रही हैं? दरअसल, लोकसभा में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले विपक्ष की वुछ महिला सांसद वेल में पहुंच गयी थीं, वुछ प्रधानमंत्री के बैठने के स्थान के बाहर खड़ी थीं। उनके हाथ में तख्ती थी। यह कोई नई बात नहीं है। अपनी बात मनवाने अथवा अध्यक्ष का ध्यान आर्कषित करने के लिए सांसद अकसर वेल में पहुंचते रहते हैं। वे अपनी बात की तख्ती लिये विरोध भी करते रहे हैं। इससे वे अपराधी नहीं बन जाते। सांसद भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और प्रधानमंत्री भी पूरे देश के हैं। इसी तरह लोकसभा अध्यक्ष भी पूरे सदन के अभिभावक होते हैं।

# संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत का संयुक्त वक्तव्य

(एजेंसी)।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वे पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते (अंतरिम समझौता) के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। आज का यह ढांचा 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) वार्ता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यह अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। यह समझौता पारस्परिक हितों और ठोस परिणामों पर आधारित पारस्परिक और संतुलित व्यापार के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित होंगी:

भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों और अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा। इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश 14257 (बड़े और लगातार वार्षिक अमेरिकी माल व्यापार घाटे में योगदान देने वाली व्यापार प्रथाओं को सुधारने के लिए पारस्परिक टैरिफ के साथ आयातों को विनियमित करना), यथा संशोधित, के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा, जिसमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी शामिल हैं, और अंतरिम समझौते के सफल समापन के अधीन, 5 सितंबर, 2025 के कार्यकारी आदेश 14346 (पारस्परिक टैरिफ की सीमा को संशोधित करना और व्यापार और सुरक्षा समझौतों को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना करना), यथा कि संशोधित किया गया है, के अनुरूप भागीदारों के लिए संभावित टैरिफ समायोजन अनुबंध में पहचानी गई वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर पारस्परिक टैरिफ हटा देगा। इसमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे और विमान के पुर्जे शामिल हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के कुछ विमानों और विमान पुर्जों पर लगाए गए उन टैरिफ को भी हटा देगा। यह टैरिफ 8 मार्च, 2018 की उद्घोषणा 9704 (संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्युमीनियम के आयात को समायोजित करना), संशोधित रूप में; 8 मार्च, 2018 की उद्घोषणा 9705 (संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के आयात को समायोजित करना), यथा संशोधित; और 30 जुलाई, 2025 की उद्घोषणा 10962 (संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे के आयात को समायोजित करना) में उल्लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को समाप्त करने के लिए लगाए गए थे। इसी प्रकार, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत को उन ऑटोमोबाइल पुर्जों के लिए अधिमान्य टैरिफ दर कोटा प्राप्त होगा जिन पर 17 मई, 2019 के उद्घोषणा 9888 (संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पुर्जों के आयात को समायोजित करना), यथा संशोधित उल्लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को समाप्त करने के लिए टैरिफ लागू था। फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्युटिकल अवयवों की अमेरिकी धारा 232 जांच के निष्कर्षों के आधार पर, भारत को जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और अवयवों के संबंध में बातचीत के माध्यम से समाधान प्राप्त होंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक दूसरे को अपने-अपने हित के क्षेत्रों में निरंतर आधार पर वरीयता बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ऐसे निर्माण नियम बनाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि समझौते के लाभ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को ही प्राप्त हों।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान करेंगे। भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने; अमेरिकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच में देरी करने या उन पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने वाली प्रतिबंधात्मक आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को समाप्त करने; और समझौते के लागू होने के छह महीने के भीतर, सकारात्मक परिणाम की दिशा में, यह निर्धारित करने पर सहमत है कि क्या अमेरिकी-विकसित या अंतर्राष्ट्रीय मानक, जिनमें परीक्षण आवश्यकताएं भी शामिल हैं, भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले अमेरिकी निर्यात के लिए चिन्हित क्षेत्रों में स्वीकार्य हैं। लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को समझते हुए, भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने पर भी सहमत है।

लागू तकनीकी विनियमों के अनुपालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों के लिए अपने-अपने मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे।

किसी भी देश द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हैं कि दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताओं में परिवर्तन कर सकता है।

# अलवर में 'बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों का सम्मेलन

**केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राजस्थान के अलवर में 'बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों के सम्मेलन' की अध्यक्षता की**

**बाघों के प्रभावी संरक्षण के लिए नीतिगत निर्णयों की व्यापक समीक्षा और क्षेत्रवार चुनौतियों की पहचान आवश्यक है: श्री भूपेंद्र यादव**

(एजेंसी)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की अब तक हुई 28 बैठकों में लिए गए सभी नीतिगत निर्णयों की समीक्षा के लिए सम्मेलन बुलाया ताकि उन निर्णयों की पहचान की जा सके जो अप्रचलित हो चुके हैं, जिन्हें लागू नहीं किया जा सका है और जिन्हें पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस पहल से बाघ संरक्षण नीति को वर्तमान समय की चुनौतियों के अनुरूप ढालने और जमीनी स्तर पर संरक्षण उपायों के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

राजस्थान के अलवर में आयोजित 'बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों के सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि भारत ने बाघ संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह व्यापक नीति समीक्षा का उपयुक्त समय है। दो दिवसीय सम्मेलन की दिशा तय करते हुए श्री यादव ने सुझाव दिया कि पिछले पांच दशकों में लिए गए नीतिगत निर्णयों को एक औपचारिक नीतिगत वक्तव्य में संकलित किया जाना चाहिए और इस मुद्दे को एनटीसीए की अगली बैठक के पहले एजेंडा आइटम के रूप में रखा जाना चाहिए।

इस सम्मेलन में राजस्थान सरकार के वन मंत्री श्री संजय शर्मा के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनटीसीए के वरिष्ठ अधिकारी, बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और देश भर के बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों ने भाग लिया।

श्री यादव ने कहा कि बाघों की संख्या का आकलन, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी बुनियादी ढांचा,

मानव-वन्यजीव संघर्ष, बाघ अभ्यारण्य निधि का उपयोग और बाघ संरक्षण की नींव को मजबूत करने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श आवश्यक है। सम्मेलन में देश में बाघ संरक्षण की समग्र स्थिति की समीक्षा की जाएगी और प्रमुख नीतिगत, प्रबंधन और परिचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

श्री यादव ने बाघों की संख्या में बदलाव सहित क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों की समीक्षा करने और देश के बाघ अभ्यारण्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए चार कार्य समूहों के गठन का भी आह्वान किया। इसके अलावा, मंत्री ने प्रतिभागियों से एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जैसे संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने को भी कहा ताकि इन शीर्ष संगठनों से प्राप्त शोध सुझावों को शामिल किया जा सके और बाघ संरक्षण में व्यावहारिक लाभ प्राप्त किए जा सकें।

चीता पुनर्वास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मंत्री जी ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक एक ऐसी जंगली प्रजाति का अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किया है जो देश में विलुप्त हो चुकी थी, और यह परियोजना अब चीतों की तीसरी भारतीय पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बोत्सवाना से चीतों का एक नया समूह फरवरी के अंत तक आने की उम्मीद है।

श्री यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना की है, जिसमें अब तक 24 सदस्य देश हैं, जबकि कई अन्य देशों ने पर्यवेक्षक का दर्जा मांगा है। उन्होंने कहा कि यूएनडीपी, आईयूसीएन, एफएओ, सीसीएफ, जीटीएफ और जीएसएलईपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी आईबीसीए के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि पहला वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईबीसीए के माध्यम से तीन प्रमुख वैश्विक चुनौतियों - बढ़ती गर्मी, भूमि का मरुस्थलीकरण और जैव विविधता का नुकसान - का समाधान किया जा सकता है।

मंत्री जी ने कहा कि बाघों और अन्य वन्यजीवों के निर्धारित क्षेत्रों से बाहर निकलने के कारण मजबूत प्रतिक्रिया प्रणालियों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि घायल जानवरों, संघर्ष से संबंधित मामलों, अनाथ शावकों और तनावग्रस्त अन्य जानवरों को समय पर और पेशेवर सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए बाघ अभ्यारण्यों के आसपास बचाव, पुनर्वास और उपचार केंद्रों के लिए एक स्पष्ट और मानकीकृत ढांचा विकसित करना आवश्यक है। इस अवसर पर मंत्री जी ने एनटीसीए की प्रचार पत्रिका -

# भारत के खिलाफ मैच खेलने के बदले पाकिस्तान ने मांगीं ये तीन रियायतें, मैच पर सस्पेंस बरकरार

(एजेंसी)।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान सरकार द्वारा मैच के बहिष्कार की घोषणा के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस फैसले पर यू-टर्न लेने के संकेत दिए हैं। हालांकि, इसके लिए बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

आखिर कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान सरकार ने टूनार्मेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के आईसीसी के फैसले के विरोध में भारत के खिलाफ मैच के

बहिष्कार का ऐलान किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस घोषणा के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। अब टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी इन शर्तों के आधार पर मैच खेलने को तैयार हो सकता है।

पाकिस्तान ने रखी ये मांग

पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी मांग आईसीसी के वार्षिक राजस्व पूल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की है। वर्तमान में पीसीबी को 34.5 मिलियन डॉलर मिलते हैं। बोर्ड का तर्क है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले आईसीसी के लिए सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें मिलने वाली फंडिंग में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पीसीबी सूत्रों के अनुसार, वे इस डेडलॉक का इस्तेमाल एक बेहतर सौदेबाजी के लिए कर रहे हैं।

भारत के साथ खेलने

पीसीबी ने आईसीसी से मांग की है कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ मध्यस्थता करे ताकि दोनों देशों के बीच रुकी हुई द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू हो सके। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2013 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। हालांकि, इस मांग का पूरा होना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बीसीसीआई का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है कि द्विपक्षीय क्रिकेट का फैसला पूरी तरह भारत सरकार के हाथ में है।

मैदान पर खेल भावना का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने मांग की है कि

# ब्लैक गॉगल्स, ब्लू शर्ट पहन आरएसएस के प्रोग्राम में सलमान खान ने की शानदार एंट्री, सब रह गए दंग

(एजेंसी)।

मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष समारोह में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। कार्यक्रम स्थल पर जैसे ही 'भाईजान' पहुंचे, सभी कैमरों का ध्यान तुरंत उनकी ओर मुड़ गया और वे मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गए। यह भव्य आयोजन फर के गौरवशाली सौ वर्षों के सफर का जश्न मना रहा है। इस कार्यक्रम में शाहरुख खान और आमिर खान को भी निमंत्रण भेजा गया था।

सलमान खान की एंट्री काफी शानदार रही, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में वह अपनी चिर-परिचित शैली में गहरे नीले रंग की शर्ट और आंखों पर चश्मा लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत का संबोधन होगा, जिसमें वे आरएसएस के सौ साल के ऐतिहासिक कार्यकाल पर प्रकाश डालेंगे।

मुंबई के नेहरू सेंटर में RSS द्वारा 'नवे क्षितिज' नामक दो दिवसीय व्याख्यानमाला का उद्घाटन शनिवार को हुआ। इसमें फिल्म निमार्ता सुभाष घई, अभिनेत्री अश्विनी भावे और दिग्गज हेमा मालिनी सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल थीं। हालांकि, सलमान खान की एंट्री ने सबकी नजरों में उन्हें कार्यक्रम का 'शो स्टॉपर' बना दिया।

इस कार्यक्रम में कई फिल्मी हस्तियां उपस्थित थीं लेकिन सलमान के पहुंचते ही, गणमान्य व्यक्ति और कैमरे स्वाभाविक रूप से उनकी ओर मुड़ गए, और उनकी उपस्थिति ने अनेकों की भौंहें चढ़ा दीं।

आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदू समाज को संगठित, अनुशासित और सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। बीते एक सदी में, फर के सदस्यों ने समाज व देश में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए हैं।

900 मेहमान आमंत्रित हैं

'नवे क्षितिज' व्याख्यानमाला के तहत, सरसंघचालक मोहन भागवत का विशेष व्याख्यान आज निर्धारित है।

# कमल हासन की बेटी श्रुति का धर्म और भगवान पर शॉकिंग खुलासा

(एजेंसी)।

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन की बेटी और जानी-मानी अभिनेत्री श्रुति हासन ने हिंदी, तमिल और तेलुगू सिनेमा में अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद श्रुति हासन ने अपनी पहचान विरासत के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सोच की अलग दिशा से बनाई है।

श्रुति हासन का आस्था को लेकर शॉकिंग खुलासा

हाल ही में श्रुति हासन ने अपने बचपन, परिवार की विचारधारा और आस्था को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया है। श्रुति हासन ने बताया कि वह एक ऐसे माहौल में पली-बढ़ीं, जहां धर्म और भगवान की पारंपरिक मान्यताओं की जगह कला, तर्क और स्वतंत्र सोच को महत्व दिया जाता था।

'हमारे घर में भगवान और धर्म की कोई जगह नहीं'

एक हालिया इंटरव्यू में श्रुति हासन ने अपने बचपन, परिवार की सोच और आस्था को लेकर खुलकर बातें की हैं। उन्होंने बताया कि वह एक ऐसे घर में पली-बढ़ीं, जहां भगवान और धर्म की पारंपरिक अवधारणा का कोई स्थान नहीं था।

'हम नास्तिक परिवार में बड़े हुए हैं'

-श्रुति हासन ने बताया कि उनका परिवार खुद को नास्तिक मानता है। घर में पूजा-पाठ, व्रत या किसी खास दिन खानपान के नियम जैसी परंपराएं नहीं थीं। उनके अनुसार बचपन से ही उनके मन में ये विचार बैठ गया था कि कला ही उनकी सबसे बड़ी आस्था है।

-श्रुति हासन ने ये भी कहा कि जब वह इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से करती हैं तो उनके पिता कमल हासन को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वह धर्म पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं।

भाषा, स्कूल और अलग तरह का बचपन

-श्रुति हासन ने बताया कि वह तमिल और हिंदी माहौल के बीच पली-बढ़ी हैं। घर में अक्सर हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती थी जबकि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थीं। इसका असर ये हुआ कि लंबे समय तक उनकी तमिल काफी कमजोर रही थी।

-एक्ट्रेस ने अपने बचपन को

सामान्य से अलग बताया। फिल्मों के सेट पर बड़ा होना, अलग-अलग कलाकारों से मिलना और असामान्य माहौल में रहना, ये सब उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। उन्होंने ये भी शेयर किया कि उनके माता-पिता पारंपरिक स्कूलिंग से नहीं गुजरे थे इसलिए पढ़ाई को लेकर घर का माहौल भी अलग था।

कमल हासन और ज्योतिष-टैटू पर विचार

-श्रुति हासन ने बताया कि अगर उनके पिता कमल हासन से ज्योतिष या ऐसे विषयों पर बात की जाए तो वह उसे तुरंत खारिज कर देते हैं। कमल हासन बेहद व्यावहारिक सोच रखते हैं और टैटू जैसी चीजें भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं।

-जहां श्रुति हासन का परिवार पारंपरिक धर्म को नहीं मानता, वहीं एक्ट्रेस ने कहा कि वह विक्का (प्रकृति से जुड़ी आध्यात्मिक मान्यताओं) में विश्वास रखती हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें महसूस होता है कि वह एक मजबूत विरासत से जुड़ी हैं। उनके लिए प्रकृति, ऊर्जा और कला ही आध्यात्मिकता का रूप हैं।

श्रुति हासन का फिल्मी करियर

श्रुति हासन 'सालारः पार्ट 1-सीजफायर', 'गब्बर सिंह', 'रेस गुर्रम', 'श्रीमान्थुडु' और 'रमैया वस्तावैया' जैसी दमदार फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अपने दम पर बनाई पहचान के साथ वह आज भी सिनेमा में काफी एक्टिव हैं। श्रुति की बातें ये दिखाती हैं कि हर कलाकार की सोच और परवरिश अलग हो सकती है और वही विविधता उन्हें खास बनाती है।

# गिरफ्तारी के बाद पटना मेडिकल कॉलेज गए सांसद पप्पू यादव, क्या है 1995 का पूरा विवाद?

(एजेंसी)।

करीब 35 साल पुराने एक मामले ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) लाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है, उसकी जड़ें साल 1995 से जुड़ी हैं।

यह मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 468 (जालसाजी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120इ (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज है।

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को सुरक्षा घेरे में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में पुलिस बल की भारी तैनाती देखने को मिली। ढटउल्ल के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने मीडिया को बताया, हमने यह उचित नहीं समझा कि वार्ड के अंदर जाकर मेडिकल प्रक्रिया की जाए, क्योंकि इससे अन्य मरीजों को परेशानी हो सकती थी। पप्पू यादव का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है और सभी जरूरी मेडिकल जांच की जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मेडिकल जांच पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 1995 में पप्पू यादव और उनके करीबी लोगों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए उनका मकान किराए पर लिया था। आरोप है कि मकान लेते समय यह बात जानबूझकर छिपाई गई कि इस आवासीय भवन का इस्तेमाल सांसद के राजनीतिक कार्यालय के रूप में किया जाएगा।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि उन्हें पहले से इस बात की जानकारी होती, तो वे कभी भी अपना घर किराए पर नहीं देते। इसी आरोप के आधार पर उस समय मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और साजिश जैसी धाराएं लगाई गईं।

मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया और अदालती सुनवाई चलती रही। हाल ही में अदालत ने पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया था, जो गिरफ्तारी से तीन दिन पहले दिया गया। इसके बाद पुलिस ने वारंट के आधार पर देर रात कार्रवाई करते हुए उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

# केशोद में आप विधायक गोपाल इटालिया और फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम की विशेष उपस्थिति में 'किसान संवाद कार्यक्रम' आयोजित किया गया

**एक प्रवीणभाई को जेल में डालोगे तो 500 प्रवीणभाई तैयार होंगे: गोपाल इटालिया**

**प्रवीणभाई की अग्नि परीक्षा ली गई और वे पूरे अंकों के साथ पास हुए: गोपाल इटालिया**

**आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज भी भाजपा नेताओं की तरह ही सोचते होंगे: गोपाल इटालिया**

**भाजपा नेताओं को भी यह भ्रम है कि अगर अअढ के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो गुजरात में भाजपा ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है: गोपाल इटालिया**

**पहली बार भाजपा के सामने खड़े होने वाले युवा मैदान में उतरे हैं और इसी वजह से अब भाजपा वाले परेशान हो गए हैं: गोपाल इटालिया**

**पूरे गुजरात का भरोसा अब अअढ पार्टी पर है: गोपाल इटालिया**

**हम पर जो झूठे केस किए गए, वह गुजरात के किसानों को पसंद नहीं आए: प्रवीण राम**

**मैं इकोजोन मुद्दे पर, घेड मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाता हूं, इसी वजह से मुझे जेल में डाला गया: प्रवीण राम**

**जो लोग वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों में से एक पर भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई: प्रवीण राम**

**रहने को कहा और शांति की अपील भी की: प्रवीण राम**

**मजबूत किया: प्रवीण राम**

**हडदड में भाजपा द्वारा किया गया षड्यंत्र था: प्रवीण राम**

**मैंने किसानों से बैठकर जिन लोगों ने हमें जेल में डाला, उन्होंने हमें और घेड और किसानों सहित पिछली सभी लड़ाइयां फिर से शुरू होंगी: प्रवीण राम**

अहमदाबाद/जूनागढ़/सुरेंद्रनगर/बोटाद/राजकोट/अमरेली/देवभूमि द्वारका/गिर सोमनाथ/पोरबंदर/गुजरात

आम आदमी पार्टी के किसान नेता और फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम 108 दिनों की जेलवास के बाद बाहर आए हैं और किसानों सहित पूरे गुजरात के लोगों के लिए अपनी मजबूत आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया के साथ किसान नेता प्रवीण राम ने आज केशोद में 'किसान संवाद' कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, किसान, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज भी भाजपा नेताओं की तरह ही सोचते होंगे कि 'अगर आजादी की बात लेकर निकलने वालों को जेल में डाल दिया जाए तो आजादी की बात ही बंद हो जाएगी।' इसी सोच के साथ अंग्रेजों ने हमारे देश के कई महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला, फिर भी आजादी आई। भाजपा नेताओं को भी यह भ्रम है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो गुजरात में भाजपा ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप एक प्रवीण राम को जेल में डालोगे तो 500 प्रवीण राम तैयार होंगे, अगर आप एक राजू करपड़ा को जेल में डालोगे तो 500 राजू करपड़ा तैयार होंगे।

आगे विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि अब तक भाजपा और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का काम करते थे और अंदरखाने पार्टी बदलते रहते थे, जिसके कारण जनता का कोई काम नहीं होता था। उन्होंने कभी भी गुजरात के आम लोगों और खासकर किसानों की आवाज नहीं सुनी। लेकिन अब गुजरात में और देश में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई और एक तरफ से ईसुदानभाई आए, एक तरफ से मैं आया, एक तरफ से प्रवीणभाई आए, एक तरफ से चैतरभाई आए और इस तरह कई लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े और भगवान के आशीर्वाद से गुजरात में आम आदमी पार्टी का मजबूत काम हुआ। इसलिए पूरे गुजरात की उम्मीद और भरोसा आम आदमी पार्टी पर टिका है। अब तक भाजपा को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब पहली बार भाजपा के सामने खड़े होने वाले युवा मैदान में आए हैं और इसी वजह से भाजपा वाले परेशान हो गए हैं। और अगर आगे भी गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिला तो भाजपा वाले हाथ में भी नहीं आएंगे।

इसके बाद आम आदमी पार्टी के किसान नेता प्रवीण राम ने अपने संबोधन में कहा कि 108 दिनों की जेलवास के दौरान केशोद की जनता सहित पूरे गुजरात की जनता ने जिस तरह मुझे और मेरे परिवार को समर्थन दिया, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हम पर जो झूठे केस किए गए, वह गुजरात के किसानों को पसंद नहीं आए। मुझे किसी व्यक्तिगत लड़ाई के कारण जेल में नहीं डाला गया, बल्कि मैं इकोजोन की लड़ाई लड़ता हूं, घेड मुद्दे पर लड़ाई लड़ता हूं, किसानों की आवाज उठाता हूं, इसी वजह से मुझे जेल में डाला गया। उन्हें लगा कि हमें जेल में डालकर वे हमें कमजोर कर देंगे, लेकिन मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हमें जेल में डालकर आप लोगों ने हमें और मजबूत किया है और भगवान करे कि आप लोग सौ साल जिएं।

इसके बाद किसान नेता प्रवीण राम ने हडदड में हुई घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि हडदड गांव में मैंने अपनी बात पूरी की और राजूभाई करपड़ा ने भी अपनी बात पूरी की और बस कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था। उसी समय पुलिस आती है और मैंने किसानों से बैठकर रहने को कहा तथा शांति की अपील की। लेकिन पुलिस वापस चली जाती है और कुछ मिनट बाद फिर लौट आती है और हमने फिर से लोगों से बैठने की अपील की। तीसरी बार जब पुलिस आई तो हेलमेट और लाठियों के साथ आई। इसके बाद पुलिस भीड़ में घुस गई। वहां जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी विवेकबुद्धि कहां चली गई? क्या पुलिस ने उकसाया नहीं? और भी गंभीर बात यह है कि जिन लोगों को उन्होंने भेजा, उनमें से कुछ ने पत्थरबाजी की, जिनमें भाजपा के लोग भी थे। इस पूरी घटना के बाद जिन 85 लोगों पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई, उनमें से एक भी व्यक्ति पत्थर फेंकता हुआ नहीं था। इन 85 लोगों के पत्थर फेंकने का एक भी वीडियो पुलिस के पास नहीं था, तो फिर पुलिस ने इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया? दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि यह भाजपा द्वारा किया गया षड्यंत्र था।

आम आदमी पार्टी गुजरात

# जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक

(एजेंसी)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू में जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, केन्द्रीय गृह मंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली, उद्योग, पर्यटन, 4ॠ और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री श्री उमर अबदुल्ला, केन्द्रीय गृह सचिव और केन्द्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, एक विकसित और समृद्ध जम्मू और कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विकास में तेजी लाने के लिए किए जा रहे निरंतर और समर्पित प्रयासों से जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल विद्युत परियोजनाओं के पूरी क्षमता को विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याण योजनाओं का 100% सैचुरेशन प्राप्त करना और सभी विकास परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि युवाओं को विकास के साथ जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और स्पोर्ट्स अकादमियों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए। इस विषय में विभिन्न स्पोर्ट्स बॉडीज से बात करके लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश की कोशिश की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि (NDDB) के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास होने चाहिएं।

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, जम्मू और कश्मीर को पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 में SASCI योजना के दायरे में लाया गया है, जिससे पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण मिल सकेंगे। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत वित्तीय अनुशासन से समय के साथ केंद्रशासित प्रदेश के वित्तीय घाटे को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश, वर्ष 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर को पूरी सहायता देती रहेगी। गृह मंत्री श्री अमित शाह का दौरा, भारत सरकार के जम्मू और कश्मीर के विकास, शांति और सुरक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

# पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री से मांफी मांगी-स्वतंत्रदेव के लिए तल्ख टिप्पणी, पूर्व सांसद ने इस बात पर मांगी

महोबा , (एजेंसी)।

पूर्व सांसद और विधायक के पिता गंगाचरण राजपूत का फेसबुक पर किया पोस्ट फिर वायरल हुआ। जलशक्ति मंत्री का काफिला रोकने व बयानबाजी करने पर चरखारी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है।

प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के 30 जनवरी को जिले के दौरे के दौरान हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी होने के बाद उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत डेमेज कंट्रोल में लगे हैं। शनिवार को उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगी है। हालांकि स्वतंत्र देव को लेकर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह जलशक्ति मंत्री पर भी निशाना साधते हुए अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पार्टी के संविधान को सर्वोपरि करार दिया है।

पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह पर सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब तक वे खुद को मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह का अभिभावक और विधायक बृजभूषण को उनका छोटा भाई बता रहे थे लेकिन शनिवार को उन्होंने कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि दोनों पक्षों को बयानबाजी करने से मना किया गया था तो मंत्री ने विधायक के खिलाफ टिप्पणी क्यों की, पार्टी इन्हें भी नोटिस दे। यदि मंत्री जी को नोटिस नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि अनुशासन की तलवार सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं का ही गला काटती है, बड़ों का नहीं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी को संबोधित करते हुए लिखा कि स्वतंत्रदेव को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के सम्मेलन में होना जरूरी था या योगी जी के साथ। किस हैसियत से मुख्यमंत्री के साथ हमेशा रहते हैं। क्या इन्होंने प्रदेशाध्यक्ष का अपमान नहीं किया क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है। यदि है तो इस बात के लिए स्वतंत्रदेव सिंह को भी सो-कॉज नोटिस जारी होना चाहिए।

पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सनातन में संतों का सम्मान सर्वोच्च है।

# केंद्रीय बजट 2026-27 एक मजबूत, लचीले और तेजी से विकास कर रहे भारत के आत्मविश्वास को दशार्ता है: हरदीप सिंह पुरी

(एजेंसी)।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज देहरादून में केंद्रीय बजट 2026-27 पर एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट 2014 के बाद से मौलिक परिवर्तन से गुजरी अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास और परिपक्वता को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि बजट विकास को बढ़ावा देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित करता है, जो भारत की उस यात्रा को रेखांकित करता है जिसमें वह "कमजोर पांच" देशों में गिने जाने से लेकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे भरोसेमंद वैश्विक विकास गाथाओं में से एक बनने तक पहुंचा है।

बजट को दूरदर्शी और सुदृढ़ीकरण उन्मुख बताते हुए श्री पुरी ने कहा कि यह पिछले दशक में रखी गई नींव पर आधारित है और भारत को वैश्विक नेतृत्व के अगले चरण के लिए तैयार करता है। उपभोग और निवेश से प्रेरित होकर, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वैश्विक वृद्धि दर लगभग 3 प्रतिशत के आसपास रहने के बावजूद, लगातार चौथे वर्ष भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।

मूल्य स्थिरता पर मंत्री जी ने 2014 से हासिल हुई तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला और बताया कि भारत ने 2025 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष मुद्रास्फीति में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की, जो लगभग 1.8 प्रतिशत थी। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच, खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति औसतन लगभग 1.7 प्रतिशत रही। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में मुद्रास्फीति का स्तर कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

श्री पुरी ने 2014 से पूंजी-आधारित विकास की ओर निर्णायक बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये है, जो 2013-14 की तुलना में 430 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दशार्ता है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटन में लगभग 500 प्रतिशत, रक्षा के लिए 210 प्रतिशत से अधिक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए लगभग 176 प्रतिशत और शिक्षा के लिए 110 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना पर किया गया खर्च विकास का एक प्रमुख इंजन बन गया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.2 रुपये का योगदान देता है।

# केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने बजट 2026 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया

युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बिजनेस शुरू करने और नौकरियां पैदा करनें के लिए दस हजार करोड़ रुपए का एक अलग फंड तैयार किया हैझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

यह बजट केवल पांच वर्ष के लिए सोचकर नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हैझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

बजट 2026 इज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेल, स्वास्थ्य, युवा, कृषि, हवाई सेवा, गांव गरीब, किसान आदि सभी क्षेत्रों को गति देगाझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ भविष्य की एआई की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया हैझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

(एजेंसी)।

वाराणसी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में पत्रकारों के साथ केंद्रीय बजट 2026झ27 पर चर्चा की। सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बजट 2026 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग सबके सशक्तिकरण का रोड मैप है।

इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश को नई उचाई दी गई है और इससे सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भारत अब रूकने वाला नहीं है, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है। इससे बड़े पैमानें पर रोजगार पैदा होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश को आधुनिक बनाने के लिए 12.2 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर)

और 53 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट दिया है, जिससे शानदार सड़कें एवं पुल बनेंगे। विदेश पढ़ने जाने वाले बच्चों और इलाज कराने वालों के लिए टीसीएस टैक्स को 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला टैक्स (कस्टम ड्यूटी) पूरी तरह माफ कर दिया है, जिससे गरीबों का इलाज सस्ता होगा। देश की हर बेटी सुरक्षित माहौल में पढ़ सके, इसके लिए बजट में हर जिले में एक "गर्ल्स हास्टल" बनाने का वादा किया गया है। साथ ही गांव कि महिलाओं के बनाए सामान को शहर और दुनिया में बेचने के लिए शी-मार्ट खोले जायेंगे।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने बताया कि पूणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे शहरों के बीच 7 नई हाई-स्पीड रेल लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे सफर का समय काफी कम हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों कि तरक्की को भी वरीयता दी गई है। हमारे किसानों के काजू और नारियल को अब पूरी दुनिया में एक "बड़े ब्रांड" की तरह बेचा जाएगा, जिससे उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। इसके साथ ही हमारे मछुआरे भाई अब समुद्र में जो भी मछली पकड़ेंगें उस पर उन्हें कोई टैक्स या ड्यूटी नही देनी पड़ेगी।

युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बिजनेस शुरू करने और नौकरियां पैदा करनें के लिए दस हजार करोड़ रुपए का एक अलग फंड तैयार किया है। कॉलेज से निकलने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिले, इसके लिए "करपोरेट मित्र" ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत दुनिया का टेक-गुरू बने, इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपए सिर्फ चिप और सेमीकंडक्टर बनानें के लिए दिए गए हैं।

छोटे उद्योगो को सहारा देने के उद्देश्य से पुरानें और बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू करने के लिए 200 पुराने औद्योगिक इलाकों को नया जीवन दिया जाएगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि दुनिया भर में मंदी है, लेकिन भारत ने अपने घाटे को 4.3% पर रोककर यह दिखा गया है कि हमारी अर्थव्यस्था चट्टान कि तरह मजबूत है।

उन्होंने बताया कि देश में 5 बड़े मेडिकल हब बनाए जाएंगे, ताकि दुनिया भर के लोग भारत में इलाज कराने आएं और यहां रोजगार बढ़े।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ था, जिसको सरकार ने इस बार 26% बढाकर 7.84 लाख करोड़ किया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह बजट केवल पांच वर्ष के लिए सोचकर नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया किया गया है। यह बजट इज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेल, स्वास्थ्य, युवा, कृषि, हवाई सेवा, गांव गरीब, किसान आदि सभी क्षेत्रों को गति देगा।

श्री कमलेश पासवान ने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ भविष्य की एआई की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए 40000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य की तैयारी के तहत मोबाइल और बैटरी बनाने के लिए जरूरी खनिजों के लिए ओडिसा और दक्षिण भारत में "स्पेशल कॉरिडोर" बनाए जाएंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

# भारत और सेशेल्स ने मुंबई में व्यवसाय गोलमेज वार्ता में समुद्री, ब्लू इकोनॉमी सहयोग पर चर्चा की

**"महासागर विजन के तहत भारत-सेशेल्स समुद्री साझेदारी प्रगाढ़ हुई, हिंद महासागर में रणनीतिक तालमेल का संकेत": सबार्नंद सोनोवाल**

प(एजेंसी)।

भारत और सेशेल्स ने मुंबई में आयोजित भारत-सेशेल्स व्यवसाय गोलमेज वार्ता में समुद्री व्यापार, ब्लू इकोनॉमी क्षेत्रों और सतत विकास में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। इसमें सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और सेशेल्स के बीच ऐसा रिश्ता है जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और जो लोगों के बीच स्थायी संबंधों से मजबूत हुआ है। इसमें समुद्री आदान-प्रदान आधुनिक कूटनीति से भी पहले का है। सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि यह साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवाद और आपसी सम्मान पर आधारित करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध में विकसित हुई है। इसमें विकास सहायता, क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया सहित कई क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

सेशेल्स के साथ भारत का जुड़ाव महासागर विजन - क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति - द्वारा निर्देशित है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, स्थिरता और सुरक्षा पर जोर देता है।

सबार्नंद सोनोवाल ने कहा, "यह साझेदारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई गति मिली है। पड़ोस-पहले जुड़ाव, महासागर-आधारित सहयोग और समावेशी विकास पर उनके जोर ने सेशेल्स सहित हिंद महासागर के द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत के जुड़ाव को स्पष्ट रणनीतिक दिशा प्रदान की है। भारत और सेशेल्स हिंद महासागर को शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के क्षेत्र के रूप में देखते हैं।"

सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह-आधारित विकास, लॉजिस्टिक्स, समुद्री सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का अनुभव सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं को पूरा कर सकता है, जबकि मुंबई का वित्तीय और फिनटेक इकोसिस्टम नवाचार और वित्तीय समावेशन पहलों का समर्थन कर सकता है।

प्रगाढ़ सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए, सबार्नंद सोनोवाल ने कहा, "ब्लू इकोनॉमी में मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, बंदरगाह विकास, समुद्री बुनियादी ढांचा, महासागर-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री अनुसंधान सहित महत्वपूर्ण गुंजाइश है। पर्यटन और आतिथ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाएं, फिनटेक, शिक्षा और कौशल विकास भी सहयोग के लिए मजबूत अवसर प्रदान करते हैं।"

भारत-सेशेल्स व्यवसाय गोलमेज वार्ता में भारत की कई व्यावसायिक संस्थाओं ने भाग लिया जो बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिनटेक और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई की बंदरगाह शहर के रूप में ताकत - इसके बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्री सेवाएं, शिपयार्ड और वित्तीय इकोसिस्टम - इसे समुद्री व्यापार और महासागर-आधारित उद्योगों में भारत-सेशेल्स सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए स्वाभाविक मंच बनाते हैं।

सबार्नंद सोनोवाल ने कहा, "मुंबई ने सदियों से दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव का प्रतीक रहा है। समुद्र, व्यापार और उद्यम से आकार लिया हुआ, भारत और सेशेल्स दो समुद्री राष्ट्र हैं जो हिंद महासागर से जुड़े हैं और समृद्धि और सतत विकास की साझा दृष्टि से एकजुट हैं। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त स्थान है।"

भारत की व्यापक आर्थिक दिशा का जिक्र करते हुए, सोनोवाल ने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसे निरंतर घरेलू मांग, सुधार-उन्मुख नीतिगत माहौल और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निवेश का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में, भारत ने कराधान, कॉर्पोरेट विनियमन और डिजिटल शासन में व्यापक सुधार किए हैं, जिससे पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी बढ़ी है।

# 'भारत की टीबी गिरावट दर विश्व स्तर पर औसत से दोगुनी है, जिसे डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दी' : श्री जेपी नड्डा

**केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने मानव रचना दीक्षांत समारोह 2025-26 को संबोधित किया**

**'दुनिया की एक-छठी आबादी वाले भारत में रहने के बावजूद मलेरिया से संबंधित मौतों में 0.6 प्रतिशत की कमी आई'**

**जेब से स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला खर्च 62 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गया: श्री नड्डा**

**स्नातकों से श्री जेपी नड्डा का आह्वान: जिस समाज ने आपको आकार दिया है, उसे वापस दें**

(एजेंसी)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने मानव रचना शैक्षणिक संस्थानों (एमआरईआई) के दीक्षांत समारोह 2025-26 को संबोधित किया, जो शैक्षणिक भव्यता और उत्साह के साथ आयोजित किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने दीक्षांत समारोह को वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन, अनुशासन और समर्पण के फलस्वरूप हासिल की गई एक उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे न केवल शैक्षणिक यात्रा की समाप्ति बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के एक नए चरण की शुरूआत भी बताया। उन्होंने स्नातक छात्रों से सशक्त मूल्यों, नैतिक आचरण और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया।

श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि स्नातक होने वाले युवाओं को अमृतकाल के दूसरे चरण में अपने पेशेवर जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त है, जो 2047 तक चलेगा, जब भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है।

# सीएम योगी की एक पहल से बदली लाखों की किस्मत, तो रामपुर के डीएम ने जनता दर्शन के दौरान जीत लिया दिल

(एजेंसी)।

सीएम योगी के विजन से रामपुर का जनता दर्शन राहत केंद्र बना है। डीएम की पहल से 3 माह में 90 अंत्योदय व 147 आयुष्मान कार्ड जारी हुए। इससे गरीबों को तत्काल इलाज और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

सरकारी योजनाओं के साथ संवेदनशील प्रशासनिक इच्छाशक्ति जुड़ जाए तो वे ज़िंदगी बचाने और जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशहाली का जरिया बन जाती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी विजन को जमीन पर उतारने के लिए रामपुर जिला प्रशासन ने जनता दर्शन में अनूठी पहल शुरू की, जो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन कर सामने आयी है। रामपुर ऐसा जिला बन गया है, जहां जनता दर्शन में न केवल आयुष्मान कार्ड बनाकर फरियादियों की गंभीर बीमारी का इलाज करवाया जा रहा, बल्कि उनकी पात्रता को चिह्नित कर अंत्योदय कार्ड बनवाकर योगी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। डीएम रामपुर अजय कुमार द्विवेदी की अनूठी पहल ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंदों के जीवन में उम्मीदों की रोशनी भर दी है, जो दर्शाती है कि प्रशासन चाहे तो बदलाव संभव है।



जनता दर्शन केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप रामपुर में सुबह 10 से 12 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाला जनता दर्शन अब केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि पीड़ितों के लिए जीवनदायिनी राहत का केंद्र बन चुका है। गंभीर बीमारियों से जूझते, गरीबी के बोझ तले दबे लोग जब सरकारी मदद की आस लेकर यहां आते हैं, तो उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि तत्काल समाधान मिलता है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने एक अभिनव व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दर्शन में जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा पीड़ित व्यक्ति की जांच की जाती है। इसके बाद गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के दस्तावेजों की जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जांच की जाती है।

# ओवैसी के 2 रुपये देने के बयान पर बोले असम के सीएम, 'मैं लेने के लिए तैयार हूं'

(एजेंसी)।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के जुबानी वार का दौर चल रहा है। सीएम के मियां भाई को परेशान करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा था कि मैं उन्हें दो रुपये दूंगा। अब इस पर हिमंता बिस्वा सरमा ने जवाब दिया है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि उन्होंने देने की बात कही है, लेकिन अब तक दिया नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि असम के विकास के लिए 2 रुपये भी लेने के लिए तैयार हैं।

मीडिया ने जब उनसे ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, '2 रुपये भी पैसा होता है। उन्होंने दिया कहां है? मैं लेने के लिए तैयार हूं, वे यहां आकर मुझे दें।' सीएम का यह बयान ओवैसी के उस तंज के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने असम सरकार की योजनाओं और आर्थिक मदद को लेकर सवाल उठाए थे।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो असम के विकास के लिए दो रुपये भी लेने के लिए तैयार हूं। आगे उन्होंने कहा, '2 रुपये लेने जाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो यहीं असम आकर मुझे पैसे दे दें। अभी तक उन्होंने पैसा तो कुछ दिया नहीं बस कहा है।' सरमा अक्सर ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब चुनावी मौसम में उनकी और सांसद ओवैसी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।

इसी बीच मुख्यमंत्री सरमा ने गुवाहाटी में राज्य सरकार की एक नई महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अश्वनी" रखा गया है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन से प्रेरित है। सरमा ने कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी के बताए रास्ते पर चलते हुए युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य के 1 लाख युवाओं को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें।'

# आंध्र प्रदेश अन्य तटीय राज्यों के साथ मिलकर भारत के ब्लू इकोनॉमी मिशन का नेतृत्व करेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

(एजेंसी)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि आंध्र प्रदेश, अन्य तटीय राज्यों के साथ मिलकर, भारत की नीली अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का नेतृत्व करेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से बार-बार ब्लू इकोनॉमी को राष्ट्रीय प्राथमिकता मिशन बनाने पर जोर देने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 मत्स्य पालन, समुद्री निर्यात, तटीय अवसंरचना और समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों को भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के केंद्र में रखकर इस दृष्टिकोण को ठोस रूप देता है।

श्री कनक दुर्गाम्मा द्वारा पवित्र की गई नगरी विजयवाड़ा में मीडिया प्रतिनिधियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 के लिए एक रणनीतिक रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारत ने स्थिरता, स्पष्टता और सतत निवेश-आधारित विकास का मार्ग चुना है।

मत्स्य पालन और समुद्री विकास से शुरूआत करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति देना और विदेशी बंदरगाहों पर मछली उतारने को निर्यात के रूप में मान्यता देना मछुआरों की आय क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह नीतिगत बदलाव खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत को एक उत्कृष्ट समुद्री राष्ट्र के रूप में मजबूती से स्थापित करता है।

# भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते से बंपर फायदा, किसानों से मोबाइल तक, पीयूष गोयल की बड़ी बातें

(एजेंसी)।

भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने देश के कारोबार, निर्यात और किसानों के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 7 फरवरी को किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि इस समझौते के तहत कई अहम भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में अब जीरो टैरिफ लगेगा, जबकि आत्मनिर्भर भारत के मजबूत सेक्टर्स में किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है।

पीयूष गोयल ने कहा कि30 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए अब खुला है। पीयूष गोयल ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद देश के 1.4 अरब नागरिक एक बार फिर दिवाली मनाएंगे। आइए जानें पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें।

1. किन भारतीय उत्पादों पर अब जीरो टैरिफ लगेगा?

पीयूष गोयल ने बताया कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कई बड़े निर्यात उत्पादों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसमें जेम्स और डायमंड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसे सेक्टर हैं, जिनमें भारत पहले से मजबूत है और अमेरिका में इनकी भारी मांग है। जीरो ड्यूटी से भारतीय कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा और निर्यात और तेज होगा।

2. खेती और किसानों को क्या बड़ा फायदा मिलेगा?

कृषि क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने राहत की खबर दी है। मसाले, चाय, कॉफी और उनसे बने उत्पाद, नारियल और नारियल तेल, वेजिटेबल वैक्स, सुपारी, ब्राजील नट, काजू, चेस्टनट के साथ-साथ कई फल और सब्जियां अमेरिका में जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ पर जाएंगी।

इसका मतलब है कि इन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, जिससे किसानों और कृषि निर्यातकों की कमाई बढ़ेगी।

3. किन फसलों पर कोई समझौता नहीं किया गया?

पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि जिन फसलों में भारत आत्मनिर्भर है, उन पर कोई रियायत नहीं दी गई है। इसमें सोयाबीन, चावल, चीनी, ज्वार, बाजरा, रागी, शहद और मूंगफली जैसे उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस समझौते में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है।

4. अमेरिका का 18% रेसिप्रोकल टैरिफ क्या मायने रखता है?

इस अंतरिम समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। पीयूष गोयल के मुताबिक यह दर भारत के पड़ोसी देशों और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं से भी कम है। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक फायदा मिलेगा।

5. किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा?

इस समझौते से टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ मशीनरी सेक्टर्स को खास फायदा होगा। मंत्री ने एक कारीगर का उदाहरण देते हुए कहा कि 18 प्रतिशत टैरिफ से नए ऑर्डर आएंगे और रोजगार बढ़ेगा।

6. एयरक्राफ्ट और पार्ट्स पर क्या बदलेगा?

अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाए गए पुराने टैरिफ हटाने पर सहमति जताई है। इससे भारतीय विमान और विमान पुर्जों के निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी और एविएशन सेक्टर को मजबूती मिलेगी।

7. क्या यह फुल ट्रेड डील की शुरूआत है?

पीयूष गोयल ने कहा कि यह अंतरिम ढांचा एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव है। आने वाले समय में दोनों देश इसे पूर्ण Bilateral Trade Agreement में बदलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

8. भारत अमेरिका से क्या खरीदेगा?

भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने की योजना जताई है। इसमें ऊर्जा उत्पाद, विमान और उनके पुर्जे, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल शामिल हैं।

# ईरान की मदद करने वाले देशों पर अमेरिका का करेगा बड़ी कार्रवाई

(एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल को मजबूत करने के लिए नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगा सकता है, जो ईरान से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करते हैं, ताकि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके।

यह कदम ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल विकास और आतंकवाद समर्थन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नए कार्यकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य ईरान के आर्थिक नेटवर्क को सीमित करना है। इसके तहत उन देशों और कंपनियों पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जो ईरान से किसी भी प्रकार का सामान खरीदते हैं या सेवाएं लेते हैं। आदेश अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा पर केंद्रित है। इसमें विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को टैरिफ लगाने और नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, ताकि ईरान की नाभिकीय और क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। ये कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विदेशी व्यापार पर कड़े नियम लागू करने की शक्ति देते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बताया है और इसी आधार पर यह कदम उठाया गया। आदेश में अधिकारों का विस्तार टैरिफ तय करने, नियम बनाने और प्रतिबंध लगाने तक किया गया है, ताकि अमेरिका के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

ट्रंप प्रशासन ने ईरान के प्रति कठोर रुख अपनाया हुआ है। 2018 में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकला था और मैक्सिमम प्रेशर नीति लागू की थी। इस नीति के तहत ईरान के विशेष गुट, जैसे [illegible], को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। नया आदेश इसी नीति को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य ईरान को नाभिकीय हथियार विकसित करने और क्षेत्रीय प्रभाव फैलाने से रोकना है। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव बढ़ाने के लिए विदेशी साझेदारों को भी दायरे में लाया गया है।

आदेश में बदलाव भी किया जा सकता है

नए आदेश में संशोधन की संभावना भी है। यदि ईरान या प्रभावित देश अमेरिकी सुरक्षा, नीति और आर्थिक हितों के अनुरूप कदम उठाते हैं या प्रतिशोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा, आदेश का उद्देश्य केवल प्रतिबंध लागू करना नहीं है बल्कि ईरान पर व्यापक जवाबदेही स्थापित करना है। इससे अमेरिकी प्रशासन को नियंत्रण का साधन मिलेगा और क्षेत्रीय अस्थिरता, आतंकवाद समर्थन तथा नाभिकीय खतरे को कम करने में मदद मिलेगी।

# दिल्ली के इस बिजी मेट्रो स्टेशन का बदल गया नाम, जानें क्या होगा?

(एजेंसी)।

दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। राजधानी दिल्ली के पूर्वी हिस्से में स्थित मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है।

इस फैसले के पीछे यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी और भ्रम को दूर करने की मंशा बताई जा रही है। क्या होगा मयूर विहार मेट्रो स्टेशन का नया नाम...



नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

मयूर विहार को अब यह स्टेशन 'श्रीराम मंदिर मयूर विहार' के नाम से जाना जाएगा। दरअसल, मयूर विहार इलाके में पहले से ही दो मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं-मयूर विहार पॉकेट-1 और मयूर विहार फेज-1। दोनों स्टेशनों के नाम काफी मिलते-जुलते होने की वजह से यात्रियों को अक्सर कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता था। कई बार यात्री गलती से गलत स्टेशन पर उतर जाते थे, जिससे उनका समय खराब होता था और असुविधा भी बढ़ जाती थी। खासतौर पर बुजुर्ग यात्रियों, नए मेट्रो यूजर्स और बाहर से आने वाले लोगों को इस वजह से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी।

नाम बदलने कीस्ट्रीट नेम्स अथॉरिटी ने दी सिफारिश

सूत्रों के मुताबिक, मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश स्ट्रीट नेम्स अथॉरिटी (SNA) द्वारा की गई है। यह अथॉरिटी दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक 29 सदस्यीय संस्था है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।

SNA का काम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में सड़कों, पार्कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों के नाम तय करना या उनमें बदलाव करना है। हालांकि, नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) इसके दायरे में नहीं आते।

स्थानीय पहचान से जुड़ा नया नाम

बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन के पास स्थित श्रीराम मंदिर इलाके की एक प्रमुख पहचान है। इसी वजह से नए नाम में स्थानीय धार्मिक और सामाजिक पहचान को शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ स्टेशन की पहचान और स्पष्ट होगी, बल्कि यात्रियों को दिशा समझने में भी मदद मिलेगी।

यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

दिल्ली में इससे पहले भी कई जगहों और मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे फैसलों का मकसद आम लोगों की सुविधा बढ़ाना, स्थानीय पहचान को मजबूत करना और भ्रम की स्थिति खत्म करना होता है।

अब मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन को 'श्रीराम मंदिर मयूर विहार' के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बदलाव से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और मेट्रो यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक होगी।

# जोक पर जांच? कॉमेडियन कुणाल कामरा और महाराष्ट्र विधान परिषद के बीच क्यों छिड़ा विवाद?

(एजेंसी)।

राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच खिंची रेखा एक बार फिर चर्चा में है। कॉमेडियन कुणाल कामरा और महाराष्ट्र विधान परिषद के बीच चल रहा विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बनाए गए एक पैरोडी गीत को लेकर शुरू हुआ यह मामला अब विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति तक पहुंच गया है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सुनवाई टालने के आरोप लगा रहे हैं।

वहीं अब देश में यहा सवाल उठने लगा है कि किसी राजनीतिक व्यंग पर इस तरह का खिंचाव या टकराव कहां तक सही है, सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या दायरा होना चाहिए?

कुणाल कामरा अपने राजनीतिक व्यंग्य और सत्ता विरोधी स्टैंड-अप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल मुंबई के खार इलाके में स्थित यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में हुए एक स्टैंड-अप शो के दौरान कामरा ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। यह गीत शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की फिल्म 'दिल तो पागल है' के एक गाने की धुन पर आधारित था।

इस पैरोडी के जरिए कामरा ने वर्ष 2022 में शिवसेना के विभाजन और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मूल शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट की बगावत पर कटाक्ष किया था। इस बगावत के चलते महाराष्ट्र की तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी और भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न भी दे दिया।



कामरा के इस मजाक के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। शिंदे गुट की शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता होटल पहुंचे और कथित तौर पर वहां तोड़फोड़ की। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छेड़ दी-क्या यह एक कॉमेडियन की अभिव्यक्ति की आजादी है या किसी जनप्रतिनिधि का अपमान?

मामला विधान परिषद तक कैसे पहुंचा?

इस विवाद के बाद भाजपा के विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने मार्च 2025 में महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। उनका आरोप था कि कुणाल कामरा और शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ "अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल किया, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची।

कामरा के पैरोडी गीत के वायरल होने के बाद बजट सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद-दोनों सदनों में इस पर हंगामा हुआ। दरेकर ने कहा कि कामरा ने एक "लोकप्रिय नेता" का अपमान किया है, जो सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कामरा का समर्थन किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसके बाद अंधारे को भी विशेषाधिकार समिति के नोटिस का सामना करना पड़ा।

कब है सुनवाई की तारीख?

महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सदस्यीय विशेषाधिकार समिति, जिसकी अध्यक्षता भाजपा विधायक प्रसाद लाड कर रहे हैं, ने कुणाल कामरा और सुषमा अंधारे को 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने के लिए बुलाया था।

समिति का कहना है कि दोनों ने उस दिन उपस्थित होने में असमर्थता जताई, जिसके बाद सुनवाई को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया।

हालांकि, कुणाल कामरा ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पुडुचेरी में रहने वाले कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा पोस्ट लिखकर कहा कि उन्होंने कभी सुनवाई टालने का अनुरोध नहीं किया।

कुणाल कामरा ने अपने पक्ष में क्या कहा?

कामरा के मुताबिक, उन्हें 23 जनवरी को जारी समन 29 जनवरी को मिला। इसके बाद उन्होंने 30 जनवरी को ईमेल के जरिए समिति को सूचित किया कि वह अपने वकील के साथ सुनवाई में उपस्थित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वह बुधवार को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उसी शाम विधान